



सत्यमेव जयते

भारत सरकार  
**GOVERNMENT OF INDIA**  
 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE  
 CHANGE**  
 एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ / **Integrated Regional  
 Office, Chandigarh**



F.No.-: 9-HRB036/2022-CHA

दिनांक: July, 2022

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन),  
 हरियाणा सरकार,  
 हरियाणा सिविल सचिवालय,  
 चण्डीगढ़।  
[fcforest@hry.nic.in](mailto:fcforest@hry.nic.in)

विषय: **Diversion of 0.014 ha. of forest land for access to Affordable Residential Plotted Colony (under Deen Dayal Jan Awas Yojna) along Sohna-Daula road km. 1-2 L&R side at Village Sohna, under forest division and District Gurugram, Haryana. (Online Proposal No. FP/HR/Approach/41473/2019)**

संदर्भ: State Government letter no. क्रमांक प्रशा-डी-तीन/9995/922 received on 24.06.2022.

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय से संदर्भांकित पत्र का अवलोकन करें जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अधीन अनुमति मांगी गई है।

2. राज्य सरकार के प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात उपर्युक्त विषय हेतु **0.014** हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए सैधांतिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरी करने पर प्रदान की जाती है।

**(A) वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा वन भूमि सौंपने से पहले अनुपालन करने की आवश्यकता है:-**

- i. प्रयोक्ता एजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाए।
- ii. **WP (C) No. 202/1995, IA No. 566** में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2011-FC (vol-I) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि की नैट प्रजेंट वैल्यू जमा करवाई जाये।
- iii. प्रयोक्ता एजेंसी भुगतान राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट [www.parivesh.nic.in](http://www.parivesh.nic.in) पर केवल ऑनलाइन माध्यम से जमा करवाएगी।
- iv. प्रयोक्ता एजेंसी को यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिपूरक शुल्क (सीए लागत, एनपीवी, आदि) वेब पोर्टल पर ऑनलाइन उतपन्न चालान के माध्यम से जमा किए जाते हैं और केवल उपयुक्त बैंक में जमा किए जाते हैं। अन्य माध्यम से जमा की गई राशि को S-I clearance के अनुपालन के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- v. सक्षम प्राधिकारी से निर्गत पर्यावरण मंजूरी (**Environment Clearance**) पत्र जमा करना होगा।
- vi. सक्षम प्राधिकारी से निर्गत **FRA** प्रमाण पत्र जमा करना होगा।

**(B) वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वनभूमि सौंपने के बाद फील्ड में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज-II अनुमोदन से पहले प्रस्तुत किया जाना है:-**

- i. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
- ii. प्रस्ताव के अनुसार कम से कम पेड़/पौधों काटे जायेंगे। प्रस्ताव के अनुसार काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या **03** से अधिक नहीं होगी।

- iii. सीए योजना के अनुसार, **100** पौधे लगाकर, **0.10** हेक्टेयर (Damdama section 4 & 5 of PLPA 190, Hailimandi (Pataudi) Range ) वन भूमि पर सीए किया जाएगा और धन उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जाएगा |
  - iv. राज्य सरकार वन भूमि को प्रयोक्ता एजेंसी को सौंपने से पहले FSI के ई-ग्रीन वॉच पोर्टल में प्रतिपूरक वनरोपण के लिए स्वीकृत degraded वन क्षेत्र की KML Files को अपलोड करेगी |
  - v. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा ।
  - vi. जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी |
  - vii. साथ लगते वन और वनभूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और वनभूमि को बचाने के लिये सभी प्रयत्न किये जायेंगे|
  - viii. स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वनभूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा |
  - ix. केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की लेआउट प्लान को बदला नहीं जायेगा |
  - x. कूड़ा कर्कट निपटान जारी योजना के अनुसार किया जायेगा |
  - xi. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय - समय पर लगाई जा सकती है |
  - xii. यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी|
  - xiii. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications), 2019 में उल्लेखित दिशानिर्देश 1.21 के अनुसार कार्यवाई की जायेगी।
  - xiv. यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।
3. उपरोक्त पैरा -2 के अधीन शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अधीन अन्तिम स्वीकृति के लिये प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा | केन्द्रीय सरकार की अन्तिम अनुमति दिये जाने तक वन भूमि का उपयोग नहीं किया जायेगा |

यह पत्र सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरांत जारी किया जा रहा है|

भवदीय,  
**Sd/-**

(राजा राम सिंह)  
उप-वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)  
IRO, MoEF&CC, Chandigarh

प्रतिलिपि:-

1. अपर वन महानिदेशक (वन), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग, अलीगंज, नई दिल्ली।([adgfc-mef@nic.in](mailto:adgfc-mef@nic.in))
2. PCCF (HoFF), Forest Department, Government of Haryana, C-18, Van Bhawan, Sector-6, Panchkula, Haryana. ([pccf-hry@nic.in](mailto:pccf-hry@nic.in))
3. Divisional Forest Officer, Forest Division District Gurugram, Haryana. ([dfo.ggn-hry@nic.in](mailto:dfo.ggn-hry@nic.in))
4. Regional Construction Pvt. Ltd., 11th Floor, Paras Twin Towers, Sector -54, Gurugram, Haryana- 122011. ([ashokraghav130@gmail.com](mailto:ashokraghav130@gmail.com))

Signed by Raja Ram Singh

Date: 13-07-2022 17:30:17

प्रेषक

उपायुक्त, गुडगांव।

सेवा में

**M/s Regional Construction Pvt. Ltd.**

क्रमांक 4113 /एस0के02 दिनांक 11-12-13

**विषय: Group Housing at village Sohna in sec-5, Distt Gurgaon, on the land measuting 17.006 acres-regarding Clearance and Forest NOC as required.**

यादि

उपरोक्त विषय पर आपके प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में।

विषयाधीन मामले में इस कार्यालय द्वारा तहसीलदार सोहना व उप-वन संरक्षक गुडगांव से रिपोर्ट प्राप्त की गई जो निम्न प्रकार है :-

तहसीलदार सोहना के कार्यालय के पत्र क्रमांक 2170/रीडर दिनांक 21.11.2013 द्वारा प्राप्त रिपोर्ट अनुसार मौजा सोहना के अराजी किला नं० 135//25/2, 136//21/2/1, 21/2/2/2, 139//1/2, 10, 11/1, 11/2, 20/1, 140//4/2, 5/1, 5/3, 6/2, 7/1, 8, 16, 17/2, 24/2, 25, 26, 179//3/2, 4, 5, 6, 7/1, 7/2, 7/3, 8, 180//10, अरावली नोटिफिकेशन 07.05.1992 के अनुसार उपरोक्त अराजी अरावली क्षेत्र से बाहर है। 07.05.1992 के नोटिफिकेशन से पूर्व अराजी भूमि की किस्म कभी भी गैर मुमकिन पहाड, गैर मु० राडा, गैर मु० बीहड, बजंड बीहड व रुन्द नही रही है।

उप-वन संरक्षक, गुडगांव के कार्यालय के पत्र क्रमांक 2590-93 दिनांक 28.10.2013 द्वारा इस कार्यालय में प्राप्त रिपोर्ट अनुसार **M/s Regional Construction Pvt. Ltd.** vide letter No. Nil dated 29.07.2013 made a request in connection with land measuring 17.006Acres having rect no. 123//25/2, 136//21/2/1, 21/2/2/2, 139//1/2, 10, 11/1, 11/2, 20/1, 140//4/2, 5/1, 5/3, 6/2, 7/1, 8, 16, 17/2, 24/2, 25, 26, 179//3/2, 4, 5, 6, 7/1, 7/2, 7/3, 8, 180//10 land located at village Sohna District Gurgaon, Applicant made a proposal to use this land for Group Housing Purpose. In Continuation of report submitted by RFO, Sohna vide letter no 279-S dated 11.09.2013 it is made clear that:

- A As per record available above said land is not part of notified Reserved Forest, Protected Forest under Indian Forest Act, 1927 specific section 4 & 5 of Punjab Land Preservation Act 1900 .
- B It is clarified that by the notification no. S.O.8/P.A2/1900/S.4/2013 dated 4<sup>th</sup> January 2013 all Revenue Estate of Gurgaon is notified u/s 4 of PLPA 1900 and S.O. 81/PA.2/1900/S.3/12 dated 19<sup>th</sup> December 2012 u/s 3 of PLPA 1900. The area is however not recorded as forest in the Government record but felling of any tree is strictly prohibited without the permission of Divisonal Forest Officer, Gurgoan.
- C If approach is required from Protected Forest by the user agency, the clearance/regularization under Forest Conservation Act, 1980 will be required without prior clearance from Forest Department, the user of Forest land for approach road is strictly prohibited M/s Regional Construction Pvt. Ltd. whose land is located at village Sohna District Gurgaon must obtain clearance as applicable under Forest Conservation Act 1980.

- D As per records available with the forest Department Gurgaon, the area does not fall in under Aravali Project Plantation done by the Forest Department under Aravali project.
- E All other statutory clearance mandated under the Environment Protection Act, 1986 as per the notification of Ministry of Environment and Forest, Government of India, dated 07.05.1992 or any other Act/order shall be obtained as application by the project proponents from the concerned authorities.
- F The project proponents will not violate any judicial order/ direction issued by the Hon'ble Supreme Court/High Courts.
- G It is clarified that the Hon'ble supreme Court has issued various judgment dated 07.05.2002, 29.10.2002, 16.12.2002, 18.03.2004, 14.05.2008 etc. pertaining to Aravalli region in Haryana, Which should be complied with.
- H It shall be the responsibility of user agency/applicant to get necessary clearances/permissions under various Acts and Rules applicable if any, from the respective authorities/Department.

रिपोर्ट सेवा में प्रेषित है।



कृते: उपायुक्त गुडगांव।



कमांक

/एस0के02 दिनांक

इसकी एक प्रति Director General, Town & Country Planning, Haryana, Chandigarh को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।



कृते: उपायुक्त गुडगांव।

Annexure-V

From: Dy. Conservator of Forests,  
Gurgaon, Haryana.

To, **M/s Regional Constructions Pvt. Ltd.**  
**Plot No. 1, Basement Shopping Complex**  
**B-1, Vasant Kunj**  
**New Delhi-110070**

No: - 2589-6

Date:- 28/10/13

**Sub.:** Clarification regarding Applicability of forest laws on Non Forest land Applied by **M/s Regional Constructions Pvt. Ltd.** land located at Village **Sohna** District-**Gurgaon**.

Applicant **M/s Regional Constructions Pvt. Ltd. Plot No. 1, Basement Shopping Complex, B-1, Vasant Kunj, New Delhi-110070** vide letter no. **Nil** dated **29.07.2013** made a request in connection with land measuring **17.006 Acres** having Rect. No. **135** Killa No. **25/2** Rect. No. **136** Killa No. **21/2/1, 21/2/2/2** Rect. No. **139** Killa No. **1/2, 10, 11/1, 11/2, 20/1** Rect. No. **140** Killa No. **4/2, 5/1, 5/3, 6/2, 7/1, 8, 16, 17/2, 24/2, 25, 26** Rect. No. **179** Killa No. **3/2, 4, 5, 6, 7/1, 7/2, 7/3, 8** Rect. No. **180** Killa No. **10** land located at village **Sohna** District Gurgaon. Applicant made a proposal to use this land for **Group Housing Purpose**. In continuation of report submitted by RFO, **Sohna** vide Letter No. **279-S** dated **11.09.2013** It is made clear that:

- As per records available above said land is not part of notified Reserved Forest, Protected Forest under Indian Forest Act, 1927 or any area closed under section 4 & 5 of Punjab Land Preservation Act, 1900.
- It is clarified that by the Notification No. S.O.8/P.A 2/1900/S.4/2013 dated 4th January, 2013, whole Revenue Estate of Gurgaon is notified u/s 4 of PLPA 1900 and S.O.81/PA.2/1900/S.3/2012 dated 19th December, 2012 u/s 3 of PLPA 1900. The area is however not recorded as forest in the Government record but felling of any tree is strictly prohibited without the permission of Divisional Forest Officer, Gurgaon The user agency is directed that construction may be done in such a manner that no tree felling be involved in the project.
- If approach is required from Protected Forest by the user agency, the clearance/regularization under Forest Conservation Act 1980 will be required. Without prior clearance from Forest Department, the use of Forest land for approach road is strictly prohibited. **M/s Regional Constructions Pvt. Ltd.** whose land is located at village **Sohna** District Gurgaon must obtain clearance as applicable under Forest Conservation Act 1980.
- As per the records available with the Forest Department, Gurgaon, the area does not fall in areas where plantations were raised by the Forest Department under Aravalli project.
- All other statutory clearances mandated under the Environment Protection Act.1986, as per the notification of Ministry of Environment and Forests, Government of India, dated 07-05-1992 or any other Act/order shall be obtained as applicable by the project proponents from the concerned authorities.
- The project proponent will not violate any Judicial Order/ direction issued by the Hon'ble Supreme Court/ High Courts.
- It is clarified that the Hon'ble Supreme Court has issued various judgments dated 07.05.2002, 29.10.2002, 16.12.2002, 18.03.2004, 14.5.2008 etc. pertaining to Aravalli region in Haryana, which should be complied with.
- It shall be the responsibility of user agency/applicant to get necessary clearances/permissions under various Acts and Rules applicable if any, from the respective authorities/Department.

Date:  
Place. **Gurgaon**.


  
**Dy. Conservator of Forest,**  
**Gurgaon.**

Endst.No.

Dated:

A copy is forwarded to:-

- Conservator of Forests, South Circle, Gurgaon for Kind information.
- D.G, T.C.P, Ayojana Bhawan, Sec-18, Madhya Marg, Chandigarh for kind information.
- Dy.Commissioner, Gurgaon for kind information. It is hereby requested to direct the user agency that construction may be done in such a manner that no tree felling be involved in the project.
- Guard File.

  
**Dy. Conservator of Forest,**  
**Gurgaon.**